IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्तमान भारतीय कृषि उद्योग– वर्णात्मक अध्ययन

मनीष परदेषी
असिस्टेंट प्रोफेसर प्रबंध संकाय
Maharishi Center For Educational Excellence College

रमा षंकर षर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर वणिज्य संकाय
Maharishi Center For Educational Excellence College

भारतीय उद्योगों के लिए आज प्रत्येक देश में यह प्रयास किया जा रहा है कि छोटे व्यवसाय एवं उद्योगों को अधिक–से–अधिक विकसित किया जाए, ताकि ये अपने–आपमें पूर्ण उद्योग का दर्जा प्राप्त कर सके, आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो सके और बड़ी इकाइयों के पूरक उद्योगों वेफ रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। संभवतः यही कारण है कि अपने देश में भी बड़ी इकाइयों के साथ–साथ छोटी इकाइयों की भी महत्ता समझी जा रही है और उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी व वित्तीय संस्थाओं को भी इस प्रक्रिया वेफ साथ संबद्ध किया जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर लोगों को इस क्षेत्रा में आने की प्रेरणा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर इकाइयों की स्थापना और इनके परिचालन में सहायता प्राप्त हो रही है। सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना की दिशा में उद्यमशीलता को यदि हम आज के विकास का मूल मंत्र मानते हैं, तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उद्यमशीलता के अभाव में विकास की किसी भी शाखा का अस्तित्व में आना संभव न होगा। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्रा में विकास की कल्पना करना उद्यमशीलता के बिना व्यर्थ है। उद्यमशीलता के साथ–साथ साहस और अभिप्रेरण का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साहस के माध्यम से ही कोई व्यक्ति सही दिशा में निर्देशित होता है। वह अथक प्रयास से अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना के विषय में जानकारी प्राप्त करता है और उसवेफ लिए क्या करना होगा? कैसे स्वीकृतियाँ मिलेंगी? किस प्रकार कोष एकत्रा होगें? एक उद्यमी के मार्ग में आनेवाली इन समस्याओं के कारण ही औद्योगिक विकास देश एवं प्रदेश में अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पाया है। इन समस्याओं के अलावा भी कुछ अन्य समस्याएँ हैं, जो कि खेतिहर श्रमिकों के मार्ग में बाधा बनकर कृषि विकास की दर धीमी करती हैं, जैसेµ

- *भारत सरकार की कृषि विकास के संदर्भ में कोई स्पष्ट व ठोस नीति नहीं रही है और कुछ उद्योगों के विकास के प्रति तो सरकार ने उदासीनता ही दिखाई है।*
- *देश में कृषि विकास की प्रक्रिया उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के प्रारंभ हुई है, पूँजी के स्रोतों में कमी है तथा विदेशी पूँजी व तकनीकी सहयोग भी पर्याप्त मात्राा में उपलब्ध नहीं है।*
- *कृषि विकास धीमी गति से होने के कारण साधनों में गतिशीलता का अभाव, मूल्यों मे अस्थिरता और विशिष्टीकरण के अभाव अर्थात् बाजार की अपूर्णता भी है।*
- भारत जैसे विकासशील देश में राजनीतिक अस्थिरता हमेशा बनी रहती है जिसके कारण कृषि विकास की गति धीमी रही है।
- देश में प्रति व्यक्तिफ आय कम होने के कारण, बचतों की कमी रहती है।
- किसी देश का कृषि विकास के प्राकृतिक साधनों एवं पूँजी पर निर्भर नहीं करता, वरन् साहसी क्षमा का होना भी आवश्यक है, जो कि भारत में प्रायः कम देखने को मिलता है।

इस सब समस्याओं के होते हुए भी कृषि विकास प्रगति पर है। कृषि संस्थान दिन–प्रतिदिन स्थापित हो रहे हैं, स्थापित होते रहेंगे और चलते रहेंगे। अतः सोचना व देखना यह है कि उद्योग अधिक–से–अधिक संख्या में लगे उद्योग लगेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी, जिससे आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आर्थिक सुदृढ़ता *बढ़ेगी, परिणामस्वरूप देश आगे बढ़ेगा, चारों ओर खुशहाली बढ़ेगी? इस खुशहाली को लाने का*

अंतरिम हल औद्योगिक विकास ही है। अब देखना यह है कि कृषि विकास तीव्र गति से कैसे संभव हो? इसके लिए विदिषा जिले के ग्रामीण खेतीहर श्रमिकों का एक आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण' चयनित किया गया है। विदिषा जिले के कृषि संबंधित उद्योगों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं, जो कि प्रदेश के कृषि विकास की गति को तीव्र करने के आधारस्तंभ तथा आर्थिक संपन्नता लाने में सहयोगी सिद्ध हुए है

***ग्रामीण उद्योगों का वर्गीकरण** – यह वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है –*

*1.**स्तर के आधार पर** –µस्तर के आधार पर ग्रामीण उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है (क) कुटीर उद्योग (ख) लघु उद्योग और (ग) वृहत उद्योग।*

कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकालीन व्यवसाय के रूप में या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। इन उद्योगों में परंपरागत विधियों तथा स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। इनके उत्पादन की बिक्री साधारणतः स्थानीय मंडियों में की जाती है। इनमें लगाए जानेवाले सयंत्र में विनियोग 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

*2.**पूँजी विनियोग में सहभागिता के आधार** – परµपूँजी विनियोग में सहभागिता के आधार पर ग्रामीण उद्योग (क) सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्योग, (ख) निजी क्षेत्रा के भारी व मध्यम उद्योग, (ग) लघु सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्योग हैं।*

सार्वजनिक क्षेत्रा में उन उपक्रमों को शामिल किया जाता है जो सरकार द्वारा नियंत्रित तथा संचालित होते हैं। सरकार का उस पर या तो पूर्ण एकाधिकार होता है या इसके अधिकांश पर सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक उपक्रमों में पूँजी का विनियोग भारी मात्रा में किया जाता है। इन उपक्रमों में आधारभूत उद्योगों को शामिल किया जाता है जैसे इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, उवर्रक, कृत्रिम रबर, सड़क यातायात आदि। इन उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास करना है।

*3.**श्रम नियोजन के आधार** –µश्रम नियोजन के आधार पर उद्योगों को तीन स्तरों में वर्गीकरण किया गया हैµ(क) बड़े पैमाने वेफ उद्योग, (ख) मध्य पैमाने के उद्योग, (ग) लघु व कुटीर स्तरीय उद्योग।*

***(क) बड़े पैमाने के उद्योग (राष्ट्रीय स्तर पर)**µइन उद्योगों का आकार विशालकाय होता है। अधिकतम ये उध्द्योग अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होते हैं। इन उद्योगों की स्थापना मुख्यतः सरकार द्वारा की जाती है। ये उद्योग समाज में भारी मात्राा में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इन उद्योगों में पूँजी का निवेश भी भारी मात्राा में किया जाता है। इन उद्योगें का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संरचना स्थापित करना तथा समाज कल्याण करना होता है।*

***(ख) मध्य पैमाने के उद्योग (राज्य स्तर पर)**µउस उद्योगों का आकार लघु तथा कुटीर उद्योगों से बड़ा परंतु बड़े पैमाने के उद्योगों से छोटा होता है। इन उद्योगों की स्थापना अधिकतम निजी क्षेत्रा के अंतर्गत की जाती है। ये उद्योग समाज के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करते हैं। इन उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन, निर्माण या सेवा प्रदान करना होता है।*

***(ग) लघु व वुफटरी स्तरीय उद्योग (जिला स्तर पर)**µलघु व कुटीर स्तरीय उद्योगों में अति लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को शामिल किया जाता है। ये उद्योग समाज में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं जिससे व्यक्तियों का जीवन स्तर प्रभावित होता है।*

*4.**कृषि उत्पादन के आधार पर** –µयदि कृषि उत्पादन वेफ आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किए जाते हैं तो इसके अंतर्गत (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, (ख) चमड़ा उद्योग तथा (ग)* हथकरघा उद्योग को शामिल किया जा सकता है।

***(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**µखाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत खाद्य पदार्थों का निर्माण संरक्षण, संवेष्ठन आदि कार्य किया जाता है। इन उद्योगों में उत्पादन, वृहत, लघु व कुटीर सभी स्तरों पर किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत निम्न उद्योग को शामिल किया गया हैµगुड़ व खांडसारी उद्योग, फल संरक्षण उद्योग, चीनी उद्योग।*

***(ख) हथकरघा उद्योग**µ*हथकरघा उद्योग भारत के प्राचीन उद्योगों में से एक है। हथकरघा द्वारा निर्मित वस्तुओं का उत्पादन उच्चकोटि का होता है। हथकरघा उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ–साथ देश के कुल कपड़ा उपलब्ध करवाने में भी हथकरघा उद्योग का सबसे अधिक योगदान रहा है।

*5.**जातिगत प्रथा के आधार** पर ग्रामीण इलाकों में जातिगत प्रथा के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता रहा है जैसेµ*

***(क) कुभकार उद्योग**µकुभकार उद्योग कुम्हार जाति द्वारा चलाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य मिट्टी से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना है। यह मुख्यतः अपने व्यवसाय में घड़े, दीये, सुराही, चिलम आदि का निर्माण करके उन्हें बाजार में सजा–धजाकर उपलब्ध करवाते हैं। कुम्हार इन उद्योगों के माध्यम से अपनी रोजी–रोटी कमाते हैं। हालाँकि यह उद्योग कापफी छोटे स्तर वेफ पाए जाते हैं।*

***(ख) लोहा इस्पात उद्योग**µलोहे से संबंधित वस्तुओं का निर्माण लुहार जाति द्वारा किया जाता है। लोहे से बर्तन, हल, तसला, फावड़े, खुदाल, दरांती, बाल्टी आदि बनाने का कार्य इस उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह व्यवसाय भी समाज में अपना विशेष महत्त्व रखता है तथा रोजगार

उपलब्ध करवाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

***(ग)* हथकरघा उद्योग**µकपड़े बनाने का कार्य जुलाहा जाति द्वारा संपन्न होता है। हथकरघा उद्योग में जुलाहा दरिया, खेस, चादर आदि को बुनने का कार्य करता है। ये जुलाहे या तो अपनी कपास पैदा करते हैं या किसानों से कपड़ा बुनने के लिए कपास खरीदते हैं। जुलाहे कपड़े बुनने के साथ कपड़े रँगाई का कार्य भी करते हैं। ये लोग कपड़े की बुनाई तथा रँगाई से अपना तथा परिवार का पालन पोषण करते हैं। कपड़े रँगने में सिद्धहस्त समूह को रंगरेज भी कहा जाता है।

कृषि संबंधित उद्योगों का आर्थिक विकास में योगदान

भारतीय आर्थिक विकास में कृषि संबंधित उद्योग एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग बड़े पैमाने पर तत्काल रोजगार प्रदान करते हैं। ये समाज में न्यायपूर्ण आर्थिक वितरण का आश्वासन देते हैं। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हैµ

कृषि संबंधित उद्योगों की स्थापना से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों पर विशेष ध्यान न दिए जाने वेफ कारण उनका पूर्णतः प्रयोग नहीं किया जाता था परंतु कृषि संबंधित उद्योग ने क्षेत्रीय संसाधनों का उचित प्रयोग करके ग्रामीण जनता को अतिरिक्त रोजगार तथा अतिरिक्त आय प्रदान की है।

कृषि संबंधित उद्योगों की स्थापना कम पूँजी में हो जाती है। जितनी पूँजी में एक सगंठित उद्योग स्थापित होता है उतनी ही पूंजी मे कई कुटीर तथा लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

परिणामस्वरूप कई गुणा अधिक रोजगार या अर्द्धरोजगार देने में ये उद्यम सक्षम होते हैं। कृषि संबंधित उद्योग बड़ी औद्योगिक इकाइयों की तुलना में अधिक व्यापक तथा बिकरे हुए हैं ये उद्योग देशभर में दूर–दूर तक फैले हुए हैं जो औद्योगीकरण को पूर्ण बनाते हैं। अतः ये औद्योगिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से उपयुक्त हैं।

कृषि संबंधित उद्योगों के समक्ष कठिनाइयाँ

*कृषि संबंधित उद्योगों ने हालाँकि काफी प्रगति की है परंतु इन उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिनका विवरण इस प्रकार है*µ

- भारत विकासशील देश है, भारतीय कारीगरों के पास उद्योगों की स्थापना तथा सुचारू *रूप से चलाने के लिए प्रायः पूँजी का अभाव है।*
- भारतीय उद्यमी को उचित मूल्य पर तथा अच्छी किस्म का कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता है।
- साधारणतः कम पूँजी के उद्योग गरीब कारीगरों द्वारा स्थापित किए जाते हैं वे प्रायः उत्पादन की अविकसित प्रणाली का ही प्रयोग कर पाते हैं।
- इन उद्योगों के समक्ष बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता की समस्या भी है। बड़े उद्योगों की वस्तुएँ सस्ती न होने के कारण छोटे उद्योगों की वस्तुएँ आसानी से नहीं बिक पातीं।
- कृषि संबंधित उद्योगों में लगे अधिकांश कारीगर अनपढ़ होते हैं जो उत्पादन की पुरानी प्रणाली अपनाते हैं। उत्पादन में सुधार या आविष्कार को ये कारीगर अंगीकृत नहीं कर सकते, परिणामस्वरूप इनके द्वारा उतपादित माल की माँग में कमी पाई जाती है।
- कृषि संबंधित उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की माँग विदेशों में भी है। वस्तुओं में हस्तकला का उपयोग होने के कारण भिन्नता पाई जाती है। परंतु निर्यात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।
- कुटीर और लघु उद्योगों में बनी वस्तुएँ मशीनों द्वारा बनी वस्तुओं की अपेक्षा कम सफाई से नहीं बनी होती हैं। परिणामस्वरूप ग्राहक कम माँग करते हैं।

ये उद्यमी यदि उत्पादित माल को बाहर जाकर मंडी में बेचते हैं तो इन मंडियों में इन्हें भुगतान समय पर नहीं मिल पाता। जिनके कारण ये वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं।

कृषि संबंधित उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- विशिष्ट प्रकार के उद्योगों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रकार की संस्थाओं तथा समितियों की स्थापना की है। जैसे केंद्रीय सिल्क परिषद 1945, अखिल भारतीय हस्तषिल्प परिषद 1952 अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग प्रमंडल 1954, नारियल जटा बोर्ड 1954 और अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1955 आदि। तकनीकी सहायता के लिए भी सरकार ने जगह जगह लघु आविष्कार बोर्ड स्थापित किए हैं।

- सरकार ने उद्योगों को समर्थ बनाने वेफ लिए अनेक औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया है जहाँ बिजली, पानी गैस, अच्छे स्थान तथा परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई है।
- भारत सरकार द्वारा इन उद्योगों को अच्छे तथा उचित दामों में कच्चे माल तथा शक्ति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है।
- श्रमिकों को प्रशिक्षण के लिए बहुत से उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा विभिन्न कोर्स के लिए भी प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
- लघु तथा वुफटीर उद्योगों की वित्त की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार कम समय में तथा उचित ब्याज पर वित्त सहायता उपलब्ध करा रही है।

• सरकार ने इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदम भी उठाए हैं जैसेµ5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए समांतर जमानत को समाप्त कर दिया गया है। सरकार की नई नीति के तहत अब लघु तथा कुटीर उद्योगों को अधिक मात्राा में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केंद्रीय बजट 2022–23 में कृषि विकास संबंधी मुख्य बातें

❖ गेहूँ और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान।

❖ देशभर में रसायनयुत्तफ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तथा गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा।

❖ नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूँजी कोष की सुविधा देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्त्वों वेफ छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन'।

संदर्भ

1. उद्यम, उद्यमी, उद्यमिता, उद्यमिता विकास संस्थान, ल•नऊ, पृ॰ 68
2. .कुटीर, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम *2006, पृ॰ 12*
3. *आर॰एन॰ अग्रवाल, इंडियन इकॉनोमी, पृ॰ 482*
4. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रगति, समीक्षा–2000, उद्योग निदेशालय कानपुर, पृ॰ 137
5. *इंद्रजीत स्मह, पफाइनेंस्मग ऑपफ स्मॉल इंडस्ट्री, पृ॰ 157*
6. *https//kplb.gov.in*

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation